एक चुनौती है गरीब किसान-मजदूर की आत्महत्या

स्वराजबीर

देश के दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं के आंकड़े, उनकी दर्दनाक हालात बयान करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल ही में 2021 के जारी किए आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ग में आत्महत्याओं का अनुपात अन्य वर्गों की तुलना में कहीं अधिक है। कुल आत्महत्याओं में से 25.6 प्रतिशत इसी वर्ग से संबन्धित हैं। उनकी दयनीय स्थिति इस बात से भी जाहिर होती है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

आत्महत्या करने वालों की संख्या 2014 में 15735 से 2020 में बढ़कर 37666 और 2021 में 42004 हो गई है। यह दुखद रुझान गरीब और हाशिएग्रस्त दिहाड़ीदार वर्ग की घोर वंचनाओं की मारी जिंदगी के प्रति समाज की उदासीनता दर्शाता है। पर रहने वाले दैनिक वेतन भोगियों का जीवन बुरी तरह पिस गया है यह समाज की उदासीनता को दर्शाता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल श्रमिकों का 85 प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत दिहाड़ीदारों का ही है।

अगर पंजाब की ही बात करें तो पिछले दिनों मानसा जिले के तीन किसानों द्वारा एक दिन में की गई आत्महत्या की ख़बर से पंजाब में कर्ज के बोझ तले दबे किसान-मजदूरों का दर्दनाक मंजर एक बार फिर सामने आया है। एक दिन में एक या दो आत्महत्याएं अब आम बात हो गयी हैं। इसके बारे में कोई आधिकारिक, प्रशासनिक या सामाजिक टिप्पणी भी नहीं सामने आ रही। झुनीर प्रखंड के झोड़कियां थाना क्षेत्र के गांव उल्क के दो एकड़ के मालिक परमजीत सिंह की दो एकड़ के मालिकाना हक वाली जमीन और तीन एकड़ लीज़ की जमीन में बोई कपास को गुलाबी सुंडी चाट गई।

सरकार या सामाजिक सहायता की आशा में कुछ समय बीत गया लेकिन आखिर में उन्होंने जिंदगी की जगह मौत को गले लगा लिया। इसी प्रखंड के गांव माखेवाला के गुरप्रीत ने आर्थिक तंगी के चलते अपने खेत में आत्महत्या कर ली। ख्याला कलां के 47 वर्षीय किसान जरनैल सिंह पर 7 लाख का कर्ज था। फसलों की तबाही और पशुओं के रोग से परेशान जरनैल ने जहरीला पदार्थ निगल कर जीवन की जोत बुझा ली। पंजाब के गरीब किसान-मजदूरों की तंगहाली का आंदजा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की उस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है जो यह बताती है कि आज देश में बीमारी और उसका इलाज न करवा पाने की वजह से परेशान होकर जान देने वाले लोगों में पंजाब का आंकड़ा सर्वाधिक है।

चुनाव के समय हर पार्टी किसानों और कार्यकर्ताओं के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में दावा करती है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार द्वारा एकत्र किए गए क़र्ज़ दस्तावेजों के अनुसार पंजाब के किसानों पर 31 मार्च 2017 तक 73777 करोड़ रुपये का संस्थागत क़र्ज़ था। निजी या साहूकारों से लिया क़र्ज़ इससे अलग था। उस समय जब किसानों का क़र्ज़ माफ करने की बात चली तो मजदूरों ने भी अपनी क़र्ज़ माफी की गुहार लगाई। सर्वेक्षण के बाद हर मजदूर परिवार पर औसतन 77 हजार रुपये के क़र्ज़ का तथ्य सामने आया। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। लंबे समय तक तो सरकारों ने कर्ज से होने वाली मौतों के तथ्यों को भी स्वीकार नहीं किया।

देश में लंबे समय से न्यूनतम मजदूरी कानून सही रूप में लागू नहीं होने के चलते दिहाड़ीदार वर्ग को उचित लाभ नहीं मिल पाया है बल्कि उनके लिए बनाई गई योजनाओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बार-बार चर्चा होती रही है। 1980 के दशक में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी के बयान को अक्सर उद्धृत किया जाता है कि दिल्ली से चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए 90 फीसदी पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है और केवल दस प्रतिशत ही सही जगह पर पहुंचता है।

गरीबों की दयनीय स्थिति 2020 में कोरोना काल में देश को देखने को मिली थी। हज़ारों मजदूरों को आनन-फानन में पैदल ही अपने घरों को लौटना पड़ा। अचानक की गई लॉकडाउन की घोषणा के कारण उनके पास बिना काम के कुछ दिनों तक जीवित रहने के लिए खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामान भी नहीं था। नोटबंदी और कोरोना की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो गया है और दिहाड़ी मजदूरों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है।

सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया था। यह दर्शाता है कि इस वर्ग के लिए जिंदगी जीने लायक रोजगार देने की गारंटी देना भी सरकार के बस में नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, मुनाफे की प्रमुखता वाले इस विकास मॉडल में मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा महसूस किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए कम से कम सौ दिनों की गारंटी वाली मानरेगा एक विशाल योजना है लेकिन सरकारें इसे लागू करने के प्रति गंभीर नहीं हैं।

कोरोना काल में सरकार ने इस योजना के लिए 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये अलग रखे थे, लेकिन उसके बाद बजट घटा दिया गया था। श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर लिए गए फैसले भी मजदूरों के खिलाफ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी मजदूरों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की जरूरत है। ऐसे रोजगार से बाजार में मांग पैदा होगी और मजदूर परिवारों को रोजगार मिलने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार पंजाब के तीन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2015 तक 16606 किसान-मजदूरों ने आत्महत्या की। सरकार ने 2015 में आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों के लिए राहत नीति तैयार की थी। इसके मुताबिक पहले दो लाख और फिर तीन लाख रुपये तत्काल आर्थिक राहत दिया जाना तय किया गया था। कृषि एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम एक साल तक मदद करने का निर्देश दिया गया था।

पीड़ित परिवार को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति को तीन महीनों के भीतर आवेदन जमा करना होता है और समिति को एक महीने के भीतर अपना निर्णय लेना होता है। पर यह नीति ज्यादातर कागजों का श्रृंगार मात्र है। कोई पीड़ित परिवारों को सहारा देता नज़र नहीं आ रहा। प्रख्यात पत्रकार पी. साईनाथ के अनुसार, यह कृषि का संकट नहीं सभ्यता का संकट है। इतनी मौतों के बावजूद सरकारी तंत्र और समाज पर कोई असर नहीं हो रहा। यह सरकार और समाज दोनों के लिए एक चुनौती है।

और अब नितिन गडकरी, जिसने जुबां चलाई वही काम से गया

बादल सरोज

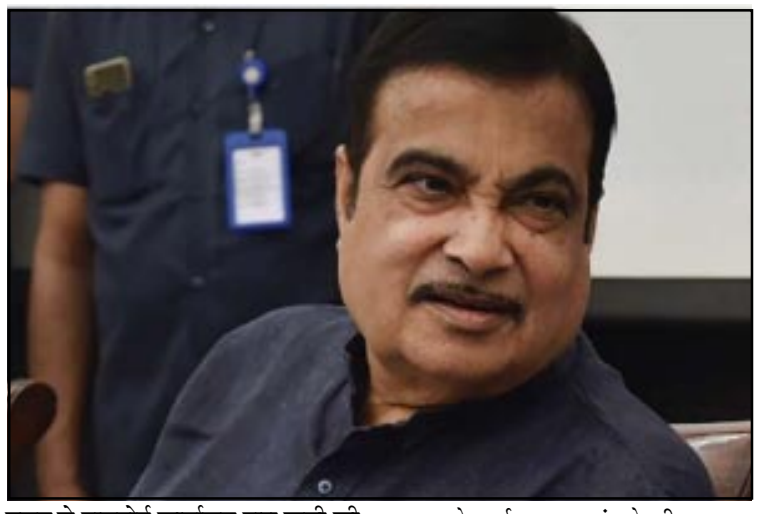

इन दिनों केंद्रीय मंत्री और खांटी नागपुरिये नितिन गडकरी बहुतई भड़भड़ाये हुए हैं। धड़ाधड़ ट्वीट पर ट्वीट कर बिलबिला रहे हैं कि "कुछ लोगों द्वारा दुष्ट राजनीतिक इरादों से उनके खिलाफ कहानियां गढ़कर एक कुटिल अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया में उनके वक्तव्यों को तोड़-मरोड़कर, मनगढ़ंत तरीके से पेश किया जा रहा है।" इन ट्वीट्स के साथ गडकरी कुछ वीडियोज भी साझे कर रहे हैं, जिन्हें बकौल उनके गलत तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है। इसी के साथ वे चेतावनी भी दे रहे हैं कि "वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में हिचकेंगे नहीं।" ऐसा करना भी चाहिए, आखिर वे केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, सत्ता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

आरएसएस के अत्यंत करीबी माने जाते हैं। उनके साथ इस तरह की छेड़खानी और धोखाधड़ी होना एक गंभीर बात है। अगर उन तक के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर सलामत कौन है ? बहुत जरूरी है कि ऐसे साजिशी गैंग की शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मगर लिखकर रख लीजिये नितिन भाऊ कोई रपट-वपट नहीं करने वाले, उन्होंने यह लोकप्रिय शेर सुना हुआ है कि ; "ये न पूछो कि किस किसने धोखे दिए/वरना अपनों के चेहरे उतर जायेंगे।" उन्हें पता है कि जाँच-वांच हुयी तो आखिर में उसके सूत्रधार उन्हीं के अपने कुनबे के बंधु-बांधव निकलेंगे।

उसकी डोरियां खुद मोदी और अमित शाह की अँगुलियों में फंसी दिखेंगी। उस कुनबे के वरिष्ठ और कुनबा प्रमुख के घनिष्ठ होने के नाते गडकरी अच्छी तरह से जानते हैं कि चरित्र हनन, झूठ गढ़न के जरिये मानमर्दन की यह कलाकारी उनके यहां की आजमाई शैली है। दुनिया भर के फासिस्ट अपने विरोधियों के खिलाफ इसका उपयोग करते रहे हैं। आरएसएस ने उसे दुधारा बनाया है; वह विरोधियों के साथ-साथ अपने ही बड़े-बड़ों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल करता रहा है, करता रहता है। पहले यह काम झूठों, कल्पित कथाओं, अर्धसत्यों की अफवाहें फैलाकर किया जाता था। नई तकनीक और सोशल मीडिया के आने के बाद अफवाहों के साथ ट्रॉलिंग-हाथ पाँव धोकर पीछे पड़ना - भी जुड़ गयी है। अब इनके पास बाकायदा सुव्यवस्थित तंत्र ; आईटी सेल की सेना है। गडकरी न इसके पहले शिकार हैं, न आखिरी; ऐसा कोई बचा नहीं, जिसका नट बोल्ट कसा नहीं।

अटल बिहारी वाजपेयी की निजता को लेकर जितनी भी कहानियां मार्केट में आईं, इन्हीं ने फैलाई। उमा भारती की जाति और नारीत्व को लेकर खुद तब के संघप्रमुख खुद तो बोले ही, जब वे पार्टी की स्वीकार्य नेता थीं तब उनके कथित निजी जीवन को लेकर अनेक वृतांत इसी कुनबे ने गढ़े और प्रचारित किये। मोदी के कार्यकाल में भी उनके नापसंद बड़े नेता इस तरह की मुहिम का निशाना बने। सुषमा स्वराज जैसी तुलनात्मक रूप से कम विवादित नेत्री भी गालियों का शिकार बनने से नहीं बचीं।

लखनऊ की एक मुस्लिम महिला को पासपोर्ट देने में उसके मुस्लिम होने की वजह से पासपोर्ट कार्यालय द्वारा खड़ी की जा रही अड़चनों की शिकायत मिलने पर विदेश मंत्री होने के नाते सुषमा स्वराज ने उसकी मदद क्या कर दी कि आई टी सेल के उकसावे पर ट्रॉल सेना के भेड़िये उनके पीछे पड़ गए। गालीगलौज की वीभत्स और भयानक मुहिम छेड़ दी थी। उनके निजी जीवन तक पर कीचड़ उछाली गयी। जिसकी सफाई देने के लिए उनके पति को सार्वजनिक बयान देना पड़ा था। इस निर्लज्ज मुहिम में उनके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री तो छोड़िये कोई मंत्री भी उनके बचाव में नहीं आया। भाजपा और संघ ने भी इसकी आलोचना नहीं की।

अपनों सहित सभी को औकात में रखने की संघ की यह आजमाई हुयी कार्यप्रणाली है। सिर्फ बाहरी ही नहीं भीतरी असहमतियों के प्रति भी उनका रुख बर्बर है। हरेन पांड्या से लेकर किसी जमाने में आरएसएस के बड़े ख़ास रहे, विहिप के पूर्व महामंत्री प्रवीण तोगड़िया के उदाहरण ताजे हैं। संजय जोशी का मामला भी छुपा हुआ नहीं हैं - जिन्हें भाजपा की कार्यसमिति से हटवाने की हठ पूरी करवाने के बाद ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए राजी हुए थे। उनकी सीडी बनवाने की पुण्याई पहले ही की जा चुकी थी। यह राष्ट्रीय स्तर के प्रसंग हैं - प्रदेशों, जिलों में इस तरह की कथाएं अनेकानेक हैं।

ध्वंस की यह परम्परा आज की नहीं है। 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद से अब तक बने अध्यक्षों में से ऐसा एक भी नहीं है जिसे सम्मान से विदा किया गया हो। जिसे आदर से याद किया जाता हो। अमित शाह के बारे में भी अभी थोड़ा इन्तजार करने की जरूरत है। इसके पहले भाजपा के पूर्वावतार जनसंघ के भी - अटल जी को छोड़ - पंडित मौलिचन्द्र शर्मा से लेकर बलराज मधोक तक इसी तरह अपमानित किये गए। अटल जी कुनबे के बाहर की अपनी लोकप्रियता और संस्थापक अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाने की वजह से बचे - बाकी कोई नहीं बचा।

ताज्जुब नहीं होगा यदि कल नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस तरह की बातें कहने की स्थिति में पहुँच जाएँ। क्योंकि एक फासिस्ट विचार पर टिका संगठन व्यवहार में भी मूलत: और अंतत: फासिस्टी होता है। उसका एकचालकानुवर्ती सांगठनिक सिद्धांत खुद अपने लोगों पर भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह वह पूरे देश और समाज पर लागू करना चाहते हैं। यही वजह है कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा का अस्तित्व ही हास्यास्पद बना हुआ है। दूसरी पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र पर ज्ञान बघारने वाली भाजपा में चुनाव भी मजाक हैं। संगठन का सबसे मजबूत और शक्ति सम्पन्न पदाधिकारी संगठन मंत्री होता है और इसकी नियुक्ति स्वयंभू सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से की जाती है।

नितिन गडकरी की ढिबरी टाइट की जा चुकी है संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद से उनके ट्वीट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान, उनकी आरती और अभ्यर्थना में कुछ ज्यादा ही भरी हुयी हैं। मगर सवाल किसी गडकरी भर का नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों की दशा उस देश के लोकतंत्र की दशा को प्रभावित करती है। यदि ऐसा उस पार्टी में हो जो सत्ता में है तब मसला और गंभीर हो जाता है।